मंदी पर सरकार की प्रतिक्रिया

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

24 अगस्त, 2019

"हाल ही में सरकार ने अपने द्वारा लिए गये कुछ निर्णयों को वापस लिया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देती है।"

एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जहाँ विकास और विचार में कमी है, वहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों का व्यापक पैकेज एक सही दिशा में उठाया गया कदम साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने विकास में मंदी की चिंताओं को संबोधित किया; बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और एमएसएमई द्वारा निवेश और खर्च के लिए फ्री फंड के बारे में बात की; एवं महत्वपूर्ण रूप से बजट में और उसके बाहर किये गये कुछ विवादित प्रस्तावों को वापस लिया, जो बाजारों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी घोषणाएं सरकार पर किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ के बिना की गई हैं। साथ ही साथ कुछ उपाय इज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए भी किये गये हैं।

हालाँकि, ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी मांग – (जीएसटी दर में कटौती) को – स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन सुश्री सीतारमण ने इस क्षेत्र को खुश करने के लिए पर्याप्त आश्वासन जरूर दिया है।

31 मार्च, 2020 तक अधिग्रहीत सभी वाहनों के लिए 15% (मौजूदा 15% के अलावा) का त्वरित मूल्यह्रास और नए वाहनों के लिए जून, 2010 में पंजीकरण शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि को स्थगित करना सकारात्मक उपाय है जो बाजार में सकारात्मक भावना को बढ़ावा देंगे और इससे मांग में बढ़ोत्तरी की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि त्यौहारी सीजन शुरू होने वाला है, बैंकों के पास 70,000 करोड़ रूपए (बजट में घोषित) के अग्रिम निधिकरण के कारण उधार देने की सुविधा बढ़ जाएगी, जिसे वे सरकार से पुनर्पूजीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे। यह, रेपो रेट से जुड़े लोन उत्पादों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, नए घरों, वाहनों और ड्यूरेबल्स को खरीदने के लिए उधार लेने वाले उपभोक्ता भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मांग को पूरा करते हुए उन पर लगाया गया ऊंचा कर अधिभार वापस ले लिया। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और उनमें निवेश करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्टार्टअप्स के शेयर्स पर होने वाली कमाई पर लगने वाले एंजेल टैक्स (Angel Tax) को सरकार ने समाप्त कर दिया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों पर लागू 'एंजेल टैक्स' को वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के तहत रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा-56 2(बी) लागू नहीं होगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंजेल टैक्स कारोबारियों के बीच एक प्रमुख मुद्दा था।

हालांकि, इसमें राहत देने के कुछ कदमों की घोषणा सरकार ने पहले भी की थी, लेकिन स्टार्टअप्स इससे संतुष्ट नहीं थे और टैक्स दायित्वों से पूरी तरह छूट की मांग कर रहे थे। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा विलंबित भुगतान में तेजी से अकेले अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर 60,000 करोड़ रुपये जारी करने की उम्मीद है।

एमएसएमई को सभी लंबित जीएसटी रिफंड का आश्वासन 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा और इस तरह के रिफंड को 60 दिनों के भीतर किया जाना इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत है। यह एमएसएमई के नकदी प्रवाह को कम करेगा जो अक्सर विस्तारित वित्त के साथ काम करते हैं।

सुश्री सीतारमण ने कहा कि सरकार 'धन सृजनकर्त्ताओं' का सम्मान करती है और सरकार के उपायों का उद्देश्य उनकी मदद करना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये उपाय जीडीपी की वृद्धि को फिर से पटरी पर ला देंगे? क्या इन उपायों से रोजगार की समस्या हल हो पायेगी? इनका जवाब अब धन सृजन करने वालों के हाथों में है। सरकार ने वही किया जो वह कर सकती थी; अब भारत की अर्थव्यवस्था की किस ओर जाएगी यह इंडिया इंक (Indian INC) पर निर्भर करता है।

GS World टीम...

भारत में मंदी के आसार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर है। निर्मला ने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है।
- उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है।

क्या कहा उन्होंने?

1. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
2. वित्तमंत्री ने टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न खत्म करने से जुड़े कर सुधारों के बारे में कहा, अब सभी कर नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करेगा।

- टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी रिटर्न एवं रिफंड को और आसान बनाया जाएगा।

3. सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये का कैपिटल तुरंत मिलेगा, ताकि बैंक, बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें।
4. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा ; भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा। एमएसएमई की एक ही परिभाषा बनाई जाएगी।
5. बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है ; रेपो रेट या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए। बैंक, घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे।
6. सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी जल्द लाएगी। मार्च, 2020 तक खरीदे गए BS4 तकनीकी के वाहन रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे।
7. सीतारमण ने घोषणा की सरकार आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सहायता भी उपलब्ध कराएगी जिससे कुल समर्थन राशि 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगी।
8. सरकार ने ऋण प्रक्रिया को आसान करने के लिए आधार नियमों को सरल बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय किया है।
9. सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मांग को पूरा करते हुए उन पर लगाया गया ऊंचा कर अधिभार वापस ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है।
10. सरकार ने एंजेल टैक्स को खत्म किया।

आर्थिक मंदी क्या है?

- जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम तीन महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं।

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- चीनी आयात में मंदी के परिणामस्वरूप कुछ देशों (विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों) को नुकसान हो रहा है, जो विभिन्न घटकों (Components) सहित अन्य तैयार माल तथा 'सप्लाई वैल्यू चेन' के लिये चीन पर निर्भर है।
- विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र के उन देशों के लिये यह एक झटका होगा, जो चीन को कच्चे माल का निर्यात करते हैं।
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस ट्रेड वॉर में पहले से ही जीडीपी का कम-से-कम 0.1% का नुकसान हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता चीनी वस्तुओं पर बढ़े हुए टैरिफ का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ रही है।

सीएसआर क्या है?

- जैसा कि हमें पता है कि कम्पनियाँ किसी उत्पाद को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं और अपनी जेबें भरतीं हैं; लेकिन इस खराब प्रदूषण का नुकसान समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों को उठाना पड़ता है क्योंकि इन कंपनियों की उत्पादक गतिविधियों के कारण ही उन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इन प्रभावित लोगों को कंपनियों की तरफ से किसी भी तरह का सीधे तौर पर मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- इस कारण ही भारत सहित पूरे विश्व में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वे अपनी आमदनी का कुछ भाग उन लोगों के कल्याण पर खर्च भी करें, जिनके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कहा जाता है।

भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में कौन कौन आता है?

- भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के नियम 1 अप्रैल, 2014 से लागू हैं। इसके अनुसार जिन कम्पनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या सालाना आय 1000 करोड़ की या सालाना लाभ 5 करोड़ की हो, तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है।
- यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। CSR नियमों के अनुसार, CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनी की शाखा और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एंजेल टैक्स धन शोधन (Money Laundering) को रोकने के लिए 2012 में शुरू किया गया था।
2. एंजेल निवेशक, ऐसे उद्यमी व धनाढ्य होते हैं जो किसी ऐसी छोटी स्टार्ट-अप कंपनी में निवेश करते हैं जिसके पास पूंजी की बेहद कमी होती है।
3. स्टार्ट-अप कंपनियों के शेयर ज्यादातर तय कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर जारी किये जाते हैं। इनसे प्राप्त अतिरिक्त इनकम पर जो टैक्स लगता है, उसे एंजेल टैक्स कहा जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements -

1. Angel Tax was started in 2012 to prevent Money Laundering.
2. Angel investors are affluent individuals who invest in small start-ups which have shortage of capital.
3. Usually the shares of start-up companies are issued at higher prices in comparison to fixed-price shares, the tax imposed on this additional income is known as Angel Tax.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Only 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे नीतिगत उपायों की चर्चा कीजिए।
(250 शब्द)

Q. Discuss the policy measures under taken by the Government of India for Protecting Indian economy from recession.
(250Words)

नोट : 23 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।